

बक्सर-भागलपुर छह लन ग्रान फिल्ड सड़क का होगा निर्माण

कैबिनेट की बैठक में इस नई परियोजना को मिली मंजूरी, राज्य सरकार अपने स्तर पर काराणी सड़क निर्माण कार्य

प्रातः किरण



पटना राज्य के बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रों बक्सर और भागलपुर को सीधे तौर पर जोड़ने के लिए एक नई छह लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा, इस ग्रीन फिल्ड सड़क की लंबाई 336 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण की मंजूरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में दी गई। कैबिनेट में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। इन निर्णयों के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग सचिव मो. सोहेल ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सड़क पीपीपी मोड पर राज्य सरकार पूरी तरह से अपने खर्च पर बनाएगी। यह सड़क बक्सर से शुरू होगी और भोजपुर, अरवल, नहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, बांका, गया, नवादा, जमुई से लखीसराय होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। इन शहरों से इस सड़क के गुजरने से पूरे इलाके की आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि बिहार

स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इसका क्रियान्वयन कराया जाएगा। इसका डीपीआर परामर्श और ट्रैजिक्शन एडवाइजर की सेवा प्राप्त करने और इस कॉरिडोर के आसपास बड़े भू-खंडों का आर्थिक प्रयोजन के विकास के लिए बीएसआरडीपीएल को प्राधिकृत करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर मंत्री परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

सचिव ने बताया कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आधारभूत प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए जापान की कंपनी टायो के साथ सूचना एवं प्रारंभिकी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ। एआई की उपयोग से विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा के विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान, प्रथमिकता निर्धारण, परि योजना मापीनीटरिंग और क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग

प्राप्त होगा।

जिला से लेकर राज्य स्तर तक मत्स्यजीवी सहकारी समिति का होगा गठन

सचिव ने कहा कि जिल से लेकर राज्य स्तर तक मत्स्यजीवी सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। इसका मकसद पिछड़े एवं वंचित वर्ग को संगठित कर राज्य स्तर तक मजबूत संरचना विकसित करना है। जिला, जिला समूह, प्रमंडल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ और राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम जिला नियोजनालय होगा उन्होंने कहा कि जिलों में मौजूद जिला नियोजनालयों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार, करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। रोजगार को

बढ़ावा देने के लिए रोजगार मेला का आयोजन, सभी प्रकार की निजी कंपनियों, उद्योगों, प्रतिष्ठानों एवं सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग इकाईयों के साथ रोजगार के लिए संपर्क, रोजगार परामर्श जैसे कार्य क्रियान्वित किए जाते हैं। अब अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम जिला नियोजनालय करने से सात निश्चय पार्ट-3 (2025-30) के अंतर्गत सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत आम लोगों और बेरोजगार युवाओं का जीवन आसान होगा।

11 हजार नलकूपों के स्थापित करने के लिए 83 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति। सात निश्चय-2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पहले से स्वीकृत 35 हजार नलकूपों को लगाने के लिए 266 करोड़ रुपये के अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार नलकूपों को स्थापित करने के लिए 83 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति सचिव ने बताया कि सात निश्चय-3 के तहत समृद्ध उद्योग संरक्षित बिहार की परिकल्पना के अंतर्गत संधुबनी के सकारी एवं दरभंगा जिले के

प्रातः किरण

रैयाम में गन्ना उद्योग विभाग की बंद चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जानी है। इन दोनों चीनी मिलों के लिए अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादक तथा गन्ना उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध किसानों को शामिल करते हुए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति दी गई है।

गोदाम निर्माण के लिए समितियों की 50 प्रतिशत अनुदान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48 हजार 200 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता के सृजन के लिए 200 मेट्रिक टन, 500 एवं 1 हजार मेट्रिक टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों की 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 फीसदी चक्रायी भूजों के रूप में कुल 34 करोड़ 95 लाख 27 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा राज्य सरकार सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और अन्य ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जनहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार को अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया (संशोधन) नियमावली-2026 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत चैनपुर ग्राम में निर्माणाधीन कोसी-मेची अंतरा-राज्यीय रिवर लिंक परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।

स्थल निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री चैनपुर ग्राम स्थित परियोजना के कैम्प कार्यालय पहुंचकर वहां परियोजना की समीक्षा की। जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. प्रदोश सिंह ने परियोजना की कार्य प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति एवं विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलेगी

प्रातः किरण

है। इसके पूरा होने से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी समृद्धि को नई गति मिलेगी। परियोजना के पूर्ण होने पर 2,14,813 हेक्टेयर कृषि भूमि को अतिरिक्त एवं सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना के माध्यम से बाढ़ के दौरान कोसी नदी के अधिशेष जल को लिंक नहर के जरिए मेची नदी तक पहुंचाया जाएगा। इससे महानाद बेसिन में जल की उपलब्धता बढ़ेगी और कोसी के बाढ़ प्रभाव को कम करने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलेगी। परियोजना से अररिया में 69,642 हेक्टेयर, पूर्णिया में 69,970 हेक्टेयर, किरानगंज में 39,548 हेक्टेयर तथा कटिहार में 35,653 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना के अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर की जल संहनन क्षमता 15,000 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक्स की जाएगी। मुख्य नहर के विस्तार के साथ 4 शाखा नहरों, 6 वितरणियों तथा आवश्यक नहर प्रणालियों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के अंतिम छोर पर लगभग 950 क्यूसेक्स जल मेची नदी में प्रवाहित होगा। परियोजना की अनुमानित कुल लागत 6,282.32 करोड़ रुपए है। इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान किसानों को कृषि कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्माण कार्य में गति, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने तथा परियोजना से जुड़े सभी कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोसी और गंडक नदियों को व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित करने के लिए समग्र योजना तैयार कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिसमें डैम एवं अन्य जल संरचनाओं के माध्यम से छोटी नदियों में भी वर्ष भर पयोग मात्रा में पानी उपलब्ध रहे। उन्होंने जल संसाधनों के समुचित उपयोग, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजना पर कार्य करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी के अधिशेष जल का समुचित उपयोग कर सीमांचल के खेतों तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में बढ़ोतरी तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

प्रातः किरण

है। इसके पूरा होने से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी समृद्धि को नई गति मिलेगी। परियोजना के पूर्ण होने पर 2,14,813 हेक्टेयर कृषि भूमि को अतिरिक्त एवं सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना के माध्यम से बाढ़ के दौरान कोसी नदी के अधिशेष जल को लिंक नहर के जरिए मेची नदी तक पहुंचाया जाएगा। इससे महानाद बेसिन में जल की उपलब्धता बढ़ेगी और कोसी के बाढ़ प्रभाव को कम करने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलेगी। परियोजना से अररिया में 69,642 हेक्टेयर, पूर्णिया में 69,970 हेक्टेयर, किरानगंज में 39,548 हेक्टेयर तथा कटिहार में 35,653 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना के अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर की जल संहनन क्षमता 15,000 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक्स की जाएगी। मुख्य नहर के विस्तार के साथ 4 शाखा नहरों, 6 वितरणियों तथा आवश्यक नहर प्रणालियों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के अंतिम छोर पर लगभग 950 क्यूसेक्स जल मेची नदी में प्रवाहित होगा। परियोजना की अनुमानित कुल लागत 6,282.32 करोड़ रुपए है। इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रातः किरण
पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ-साथ, हिंसक प्रदर्शन, सामुदायिक तनाव, सड़क जांच और सरकारी संपत्ति पर हमले जैसी आकस्मिक परिस्थितियों से प्रभावित इलाके से निपटने के लिए सभी जिलों में जिला दंगा निरोधी दस्ता गठित करने का फैसला किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को इसकी विस्तृत कार्ययोजना जारी की गई है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, प्रत्येक जिले एवं अनुमंडल स्तर पर दंगा निरोधक इकाई का गठन किया जा रहा है।

इन दस्तों में प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी, प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी, आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा एवं एंबुलेंस सहायता दल, वीडियोग्राफी एवं दस्ताधिकरण के लिए नामित कर्मी, संचार एवं रिजल्ट बल तथा लाठी दस्ते में ओआरएम के सिपाही शामिल होंगे। प्रत्येक कंपनी में तीन प्लाटून होंगे। हर प्लाटून में अश्व गैस दस्ता, लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, चालक और वायरलेस ऑपरेटर समेत कुल 47 कर्मी होंगे। प्रत्येक प्लाटून के साथ दो वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह राज्य में कुल 49 कंपनियों के दंगा निरोधी दस्ते का गठन किया जाएगा और इनके लिए कुल 294 वाहन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। जिलों को तीन श्रेणियों में बांटकर बल की तैनाती की जाएगी। श्रेणी ए में 18 वाहन जिले को तीन कंपनियों एवं 12 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर और बेगूसराय को दो-दो कंपनियां तथा 12-12 वाहन दिए जाएंगे। श्रेणी ब्वाबीहू में नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, वैशाली, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मिश्रपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, केशगंज, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया शामिल हैं। इन जिलों में एक-एक कंपनी और छह-छह वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रेणी ह्वासीहू में अरवल, शिवहर, बगहा, लखीसराय, शेखपुरा और नवगछिया को एक-एक प्लाटून तथा दो-दो वाहन दिए जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि किसी जिले में दंगा या हिंसक स्थिति की सूचना मिलते ही जिला निर्यंत्रण कक्ष द्वारा तत्काल सूचना प्रसारित की जाएगी। इसके बाद दंगा निरोधी दस्ता 20 मिनट के भीतर निर्धारित स्थान के लिए रवाना किया जाएगा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीम वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति का लगातार आकलन करेगी और आवश्यकता के अनुसार नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। दंगा निरोधी दस्ते को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पटना महिलाओं और बालिकाओं की आवश्यकताओं को सरकारी योजनाओं और बजट में बेहतर स्थान देने तथा योजनाओं से उन्हें मिलने वाले वास्तविक लाभ का लैंगिक दृष्टिकोण से आकलन करने की दिशा में बिहार सरकार ने पहल तेज की है। इसी उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को निगम के सभागार में लैंगिक उत्तरदायी बजट निर्माण विषय पर राज्य स्तरीय समीक्षा सह संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में योजना निर्माण से

परिणाम का मूल्यांकन तक महिलाओं की जरूरतों को केंद्र में रखने पर जोर दिया गया।

अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने कहा कि लैंगिक बजट निर्माण को केवल महिलाओं के लिए बजट में राशि निर्धारित करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण और समावेशी विकास से जोड़कर देखें। जो आवश्यकता है। महिला कल्याण के साथ महिलाओं के विकास, आर्थिक सहभागिता और उद्यमिता को भी इसके महत्वपूर्ण आयाम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सही दिशा में

करते समय महिलाओं की वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं को शामिल करने पर विशेष जोर दिया। स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाते समय यही समझना जरूरी है कि महिलाओं को सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उनका प्रामाणिक आवश्यकताएं क्या हैं। अगर मुख्य सचिव ने महिलाओं के स्तर से घर और परिवार के लिए किए जाने वाले अवैतनिक श्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योगदान अक्सर दिखाई नहीं देता।

प्रातः किरण
पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ-साथ, हिंसक प्रदर्शन, सामुदायिक तनाव, सड़क जांच और सरकारी संपत्ति पर हमले जैसी आकस्मिक परिस्थितियों से प्रभावित इलाके से निपटने के लिए सभी जिलों में जिला दंगा निरोधी दस्ता गठित करने का फैसला किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को इसकी विस्तृत कार्ययोजना जारी की गई है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, प्रत्येक जिले एवं अनुमंडल स्तर पर दंगा निरोधक इकाई का गठन किया जा रहा है।

इन दस्तों में प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी, प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी, आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा एवं एंबुलेंस सहायता दल, वीडियोग्राफी एवं दस्ताधिकरण के लिए नामित कर्मी, संचार एवं रिजल्ट बल तथा लाठी दस्ते में ओआरएम के सिपाही शामिल होंगे। प्रत्येक कंपनी में तीन प्लाटून होंगे। हर प्लाटून में अश्व गैस दस्ता, लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, चालक और वायरलेस ऑपरेटर समेत कुल 47 कर्मी होंगे। प्रत्येक प्लाटून के साथ दो वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह राज्य में कुल 49 कंपनियों के दंगा निरोधी दस्ते का गठन किया जाएगा और इनके लिए कुल 294 वाहन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। जिलों को तीन श्रेणियों में बांटकर बल की तैनाती की जाएगी। श्रेणी ए में 18 वाहन जिले को तीन कंपनियों एवं 12 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर और बेगूसराय को दो-दो कंपनियां तथा 12-12 वाहन दिए जाएंगे। श्रेणी ब्वाबीहू में नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, वैशाली, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मिश्रपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, केशगंज, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया शामिल हैं। इन जिलों में एक-एक कंपनी और छह-छह वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रेणी ह्वासीहू में अरवल, शिवहर, बगहा, लखीसराय, शेखपुरा और नवगछिया को एक-एक प्लाटून तथा दो-दो वाहन दिए जाएंगे।

पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि किसी जिले में दंगा या हिंसक स्थिति की सूचना मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा तत्काल सूचना प्रसारित की जाएगी। इसके बाद दंगा निरोधी दस्ता 20 मिनट के भीतर निर्धारित स्थान के लिए रवाना किया जाएगा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीम वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति का लगातार आकलन करेगी और आवश्यकता के अनुसार नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। दंगा निरोधी दस्ते को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

पटना महिलाओं और बालिकाओं की आवश्यकताओं को सरकारी योजनाओं और बजट में बेहतर स्थान देने तथा योजनाओं से उन्हें मिलने वाले वास्तविक लाभ का लैंगिक दृष्टिकोण से आकलन करने की दिशा में बिहार सरकार ने पहल तेज की है। इसी उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को निगम के सभागार में लैंगिक उत्तरदायी बजट निर्माण विषय पर राज्य स्तरीय समीक्षा सह संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में योजना निर्माण से

परिणाम का मूल्यांकन तक महिलाओं की जरूरतों को केंद्र में रखने पर जोर दिया गया।

अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने कहा कि लैंगिक बजट निर्माण को केवल महिलाओं के लिए बजट में राशि निर्धारित करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण और समावेशी विकास से जोड़कर देखें। और आवश्यकता है। महिला कल्याण के साथ महिलाओं के विकास, आर्थिक सहभागिता और उद्यमिता को भी इसके महत्वपूर्ण आयाम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सही दिशा में

करते समय महिलाओं की वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं को शामिल करने पर विशेष जोर दिया। स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाने समय यह समझना जरूरी है कि महिलाओं को कैसे सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उनको प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं। अगर मुख्य सचिव ने महिलाओं के स्तर से घर और परिवार के लिए किए जाने वाले अवैतनिक श्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योगदान अक्सर दिखाई नहीं देता।

मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर-पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल की तैयारी तेज

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी और संचचनात्मक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। बड़े शहरों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए आसपास के शहरों के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर बिहार की प्रमुख नगरी मुजफ्फरपुर को राजधानी पटना से नमो भारत रैपिड रेल सेवा से जोड़ने की तैयारी तेज होने की



बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर और पटना के बीच प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। इनमें कारोबारी, नौकरीपेशा

लोगों के साथ छात्र और मरीज भी शामिल हैं। ऐसे में दोनों शहरों के बीच तेज रेल सेवा शुरू होने की सूचना यात्रियों के लिए राहत भरी

खबर है। इस परियोजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की मदद से आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर और पटना के बीच करीब आधा दर्जन मेमू के अलावा कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होता है। इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी बसें भी दोनों शहरों के बीच चलती हैं। इसके बावजूद सड़क और रेल मार्ग से यात्रा पूरी करने में सामान्यतः ढाई से तीन घंटे तक का समय लग जाता है। प्रस्तावित नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू होने पर मुजफ्फरपुर–पटना के बीच यात्रा का समय करीब

चलती कार में लगी आग, चालक की सूझबूझ से सात लोगों की बची जान

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। मुशहरी थाना क्षेत्र के नरौली चौक के समीप दुर्गा मंदिर के सामने बुधवार को चलती एक्सयूभी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी धू-धूकर जलने लगी। हालांकि, चालक की सूझबूझ से कार में सवार सभी सात लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वाहन मालिक कुमार चंद्रमणि अपने परिवार के साथ सकरा

थाना क्षेत्र के बलुआ गांव स्थित घर में आयोजित पूजा में शामिल होने जा रहे थे। परिवार के सात सदस्य बीएफपी-6 को स्थित आवास से कार से निकले थे। इनमें दो बच्चे और चार महिलाएं भी शामिल थीं। कार में सवार अनुपम कुमारी ने बताया कि नरौली चौक के पास पहुंचते ही स्टयरिंग के पास से अचानक धुआं निकलने लगा और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। कुछ ही देर में धुआं तेजी से फैल गया और आग बढ़ने लगी। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तत्काल कार रोक दी और सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर

निकाल लिया। सभी लोगों के बाहर निकलने के बाद आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। कार को जलता देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हाताहत होने का सुचना नहीं है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

फेविविक् से एटीएम के कैश रलॉट को चिपकाकर 85 हजार की टगी, मैनेजर हुआ शिकार

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। कांटी थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने टगी का नया तरीका अपनाते हुए एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मैनेजर को अपना शिकार बना लिया। सदातपुर स्थित पहाड़पूर शनि मंदिर के सामने क्लेनो क्लेनो लगे टाटा इंडिकैश एटीएम में छेड़छाड़ कर अपराधियों ने प्रतिष्ठान के करेंट अकाउंट से 85 हजार रुपये उड़ा लिए। टगी का पता तब चला, जब खाते से लगातार रकम कटने के मैसेज मोबाइल पर आने लगे। जानकारी के अनुसार, प्रतिष्ठान के मैनेजर कबीन्द्र कुमार एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे। उन्होंने कांटी मशीन में डालकर पिन और निकासी की रकम दर्ज की, लेकिन पैसे बाहर नहीं निकले। इसके बाद वह बिना रकम निकाले वहीं से लौट गए। इसी दौरान प्रतिष्ठान के मालिक के मोबाइल पर खाते से लगातार रकम

कटने के संदेश आने लगे। मालिक ने जब मैनेजर से इस संबंध में पूछा तो वह भी हैरान रह गए। इसके बाद मालिक ने एटीएम पर पहुंचकर जांच की। मशीन के कांर्ट स्लॉट और कैश निकलने वाली जगह पर फेविविक् जैसा चिपचिपा पदार्थ लगा मिल। कैश निकलने वाले हिस्से का ढक्कन भी बुरी तरह चिपका हुआ था। इससे साइबर टगी का शक गहरा गया। एटीएम कार्ड को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्ड मशीन में फंसा रहा। दो लोगों के प्रयास के बावजूद कार्ड बाहर नहीं निकल सका। इस बीच खाते से नौ बार में कुल 85 हजार रुपये की निकासी हो गई। अपराधियों ने आठ बार 10-10 हजार रुपये और अंतिम बार पांच हजार रुपये निकाल लिए। एटीएम पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं होने के कारण पीड़ित को तत्काल सहायता भी नहीं मिल सकी। इसके बाद उन्होंने एटीएम कार्ड के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर कार्ड ब्लॉक

कराया। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी संपर्क किया। वहां से कार्ड ब्लॉक कराने की जानकारी दी गई, लेकिन शिकायत दर्ज कराने में तत्काल मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद कांटी थाना को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की ओर से डायल 112 की टीम को भेजकर औपचारिक जांच कराई गई। टीम ने मामले को साइबर अपराध से जुड़ा बताते हुए आगे की कार्रवाई के लिए साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करने की बात कही। पीड़ित ने अगले दिन अपने दोनों मोबाइल नंबरों से साइबर हेल्पलाइन पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। बाद में दूसरे मोबाइल नंबर से संपर्क करने पर करीब एक घंटे तक पूछताछ के बाद साइबर टगी को शिकायत दर्ज की जा सकी। मामले के बाद एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों की निगरानी पर भी सवाल उठने लगे हैं।

मुजफ्फरपुर राज्य सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजना सहयोग शिविर अब कागजो में सिमट कर रह गई है। सरकार के अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं जागरूकता के अभाव में आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे सरकार की इस योजना को धक्का लग रहा है। मंगलवार को प्रखंड के तीन पंचायत उनसर, आदिगोपालपुर, व रामदास मझौली में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। तीनों पंचायतों के शिविर में जहाँ अधिकारी तो बैठे रहे लेकिन जनता नहीं पहुँच पाई। इसको लेकर मझौली पंचायत के मुखिया पति सह समाजसेवी केदार पासवान ने बताया की पूर्व से सहयोग शिविर का आयोजन 25 अगस्त का आयोजन होना था लेकिन अचानक से मंगलवार की तिथि निर्धारित कर दी गई इस कारण व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया इस कारण लोग कम पहुँच पाए। वहीं आदिगोपालपुर पंचायत के मुखिया पति लखेद्र पासवान ने बताया कि आनन फानन में शिविर का आयोजन किया गया है। जिस कारण पंचायत के लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। इस कारण काफी कम लोग शिविर में पहुँचे। वहीं उनसर की मुखिया सरोज कुमारी ने बताया की अल्प समय में जो तैयारी हो सकी किया गया है। पूर्व से निर्धारित समय से पहले होने के कारण ज्यादातर लोगों तक शिविर की जानकारी नहीं पहुँच पाई। वहीं बीडीओ जूही कुमारी ने बताया की पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोगों को जानकारी दी गई थी। सभी शिविरों में लोग आये थे। कुछ राजनितिक आरोप प्रत्यारोप के कारण भी समस्या आई है। जीविका के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई थी।

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के प्रकाशन के लिए ग्राम और नगर निर्देशिका से जुड़े सामाजिक-आर्थिक एवं नागरिक सुविधाओं के आंकड़ों का डिजिटल संकलन एक से 30 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। इस बार पहली बार भौतिक प्रपत्रों के बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के अवर सचिव रणविजय कुमार ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्र पदाधिकारी मोबाइल ऐप के

माध्यम से नागरिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद चार्ज अधिकारी वेब पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन करेंगे। जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देश के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में नागरिक सुविधाओं से जुड़े आंकड़ों के लिए 31 दिसंबर 2025 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। सर्वे के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, बैंकिंग, परिवहन सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र कार्य एक से 30 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद चार्ज अधिकारियों को 20 सितंबर तक आंकड़ों का सत्यापन पूरा करना होगा। निदेशालय स्तर पर आंकड़ों की जांच और परीक्षण की प्रक्रिया 30 अक्टूबर

चौरी के मोबाइल में सिम लगाना पड़ा भारी, भोपाल जीआरपी ने मोतीझील से युवक को दबाचा

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील इलाके से मंगलवार को भोपाल जीआरपी की टीम ने चौरी के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे युवक नसीम अख्तर को गिरफ्तार किया। मोबाइल की जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए जीआरपी की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची थी। नगर थाना पुलिस के सहयोग से मोतीझील स्थित एक मार्केट में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा गया, जहां वह सिलाई का काम करता था। जानकारी के अनुसार, कांटी थाना क्षेत्र के चकमुरमुर दामोदरपुर गांव निवासी नसीम अख्तर पर आरोप है कि वह चौरी के मोबाइल में अपना सिम लगाकर उसका इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल की जांच के दौरान भोपाल जीआरपी को उसके इस्तेमाल की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल की टावर लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान मोबाइल की टावर लोकेशन कांटी के दामोदरपुर स्थित नसीम अख्तर के घर के आसपास मिली। इसके बाद भोपाल जीआरपी की टीम उसके घर पहुंची। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि नसीम काम के सिलसिले में मोतीझील गया हुआ है। इसके बाद जीआरपी टीम ने नगर थाना पुलिस से संपर्क किया और मोतीझील पहुंची। नगर थाना पुलिस के सहयोग से जीआरपी टीम ने संबंधित मार्केट में छापेमारी कर नसीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे काफी देर तक पूछताछ की और चौरी के मोबाइल के इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी को चौरी का मोबाइल कहाँ से मिला और इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह शामिल है या नहीं। आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोपाल जीआरपी आरोपी को अपने साथ ले जा सकती है। मामले में पुलिस चौरी के मोबाइल से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

इफको किसान मित्र समूह प्रशिक्षण में किसानों को नैनो उर्वरक के इस्तेमाल की दी जानकारी

प्रातः किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। इफको मुजफ्फरपुर की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र, तुर्की के सभागार में इफको किसान मित्र समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि केवीके तुर्की के कार्यक्रम समन्वयक सह प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एसके राय और इफको केबिया के उप क्षेत्र प्रबंधक सुजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डॉ. एसके राय ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर इफको नैनो उर्वरक और जल में घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल कर कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कृषि

सोशल मीडिया पर शिक्षामंत्री पर अन्यायित टिप्पणी करने के आरोप में शिक्षक निलंबित

मुजफ्फरपुर। जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित उत्कमित मध्य विद्यालय साढ़ा कन्या के विंशिट शिक्षक राजेश कुमार को सोशल मीडिया पर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कथित राजनैतिक और अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबन के साथ ही शिक्षक को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखा गया है। सोशल मीडिया पर शिक्षक राजेश कुमार की ओर से शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के संबंध में की गई कथित टिप्पणी विभाग के संज्ञान में आई। विभाग ने इसे सरकारी सेवक के आचरण से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय की ओर से 17 अगस्त 2026 के माध्यम से शिक्षक राजेश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

देश दुनिया की ताजा तरोन खबरें पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें

 @Pratahkiran

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

 www.pratahkiran.com

</

नौकरी के साथ जीवन की तैयारी भी जरूरी है

सरकारी नौकरा जीवन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह जीवन का सब कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि वेतन, पद, पदेनवित्त और सरकारी लाभ अच्छे हैं, लेकिन उनका परिवार, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास और सेवाविनवृत्ति के बाद के भविष्य को तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, अपने घर की समस्याएं बनाएं। चाहे गांव हो या शहर, अपना घर होने से स्थिरता और आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। सरकार द्वारा आवास मिलना अच्छी बात है, लेकिन यह आपके जीवन का आधार भी होना चाहिए। अपना घर होने से नौकरी छूटने की स्थिति में आपको और आपके परिवार को काफी आसानी होगी। काम के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें, लेकिन अपना पूरा जीवन कार्यस्थल को न समर्पित करें। यह न सोचें कि आपके बिना कंपनी की चल सकती है। इनमें से प्रत्येक भूमिका कोई और निभा सकता है, लेकिन आपको के साथ बिताएं उन पलों को आप कभी वापस नहीं पा सकते। अपनी छुट्टियों और अवकाश का आनंद लें, आराम करें या परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे समय बिताएं, अपना ख्याल रखें, यात्रा करें, सीखें और जीवन का आनंद लें। पदेनवित्त को ही सफलता का एकमात्र मापदंड न बनाएं। अभ्यास करें और अपनी क्षमताओं को विकसित करें, ज्ञान बढ़ाएं और अपने हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त करें। पदेनवित्त मिनिमम पर उसका लाभ उठाएं। अगर पदेनवित्त नहीं मिलती है, तो निराशा होने के बजाय अपने आत्मसम्मान को कम न होने दें। व्यक्तिगत विकास किसी पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऑफिस की गणराज्य, राजनीति और नकारात्मक बातों से दूर रहें। बड़ों का आदर करें, लेकिन चापलूसी को अपना पेशा न बनाएं। शक्तिशाली लोगों को खुश करने से शक्ति सम्मान मिल सकता है, लेकिन ये चीजें स्थायी सम्मान नहीं दिलातीं। अपने आत्मसम्मान, आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखें। हमेशा दूसरों से अपनी तुलना न करें, बल्कि खुद से प्रतियोगिता करें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक स्तर सुधार के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर यह किसी को हराने की भावना से प्रेरित हो, तो कुछ लोग बेवजह तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपको को खुद से मुकाबला करना चाहिए, किसी और से नहीं। अपने वित्त का प्रबंधन करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपनी तनख्वाह पर निर्भर न रहें और उससे ही सब कुछ पाने की उम्मीद न रखें। अपनी आय, दायित्वों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर बचत और निवेश योजनाएं बनाएं। जब आप दूसरी आय या व्यवसाय के बारे में सोचें, तो सुनिश्चित करें कि यह सेवा नियमों और आपके प्रेशर कर्तव्यों के अनुरूप हो। निर्यात रूप से बचत करने की आदत डालें। आवश्यक कर्ज और जीवनशैली में बेवजह की बढ़ोतरी से बचें। शिक्षा प्राप्त करें, किसी लाभकारी संपत्ति खरीदने या किसी सुनिर्वाचित उद्यम के लिए उधार लेना भले ही स्वीकार्य हो, लेकिन अपनी मनचाही जीवनशैली बनाए रखने के लिए कम लेना उचित नहीं है। निजी जीवन की बातें साझा न करें। कार्यालय में निजी संबंधों, आर्थिक मामलों, परिवारिक मुद्दों और विवाद पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने निजी जीवन के बारे में जो बातें आप साझा करते हैं, उससे नहीं, बल्कि अपने आचरण, परिवार रवैये और ईमानदारी से अपने सहकर्मियों, सहयोगियों और निवेशकों को का सम्मान करें। अपने करियर की शुरूआत से ही अपनी सेवाविनवृत्ति की योजना बनाएं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि सेवाविनवृत्ति 40 या 50 वर्ष की आयु में ही हो। वास्तव में, सेवाविनवृत्ति का अर्थ है उन दिनों के लिए वित्तीय, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना जहां काम, चाहे अच्छा हो या बुरा, समाप्त हो जाएगा। सेवाविनवृत्ति के बाद जीवन को अपूर्ण बनाने के लिए रूचियों और गतिविधियों की योजना बनाएं। यह लेखन, अध्यापन, खेलें, छोटो व्यवसाय चलाना, सामाजिक कार्य, यात्रा, पढ़ना या कोई अन्य अच्छी गतिविधि हो सकती है। काम करते समय धीरे-धीरे कुछ संभव से आपको उसका अनुभव मिलेगा। आप अपने दाएं पाखण्डों की यह संभव है या नहीं। अपनी दिनचर्या तय करने के लिए सेवाविनवृत्ति का हवाला न करें। दशकों तक काम करने के बाद, सेवाविनवृत्ति के बाद जीवन में ढलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई और निर्यात दिनचर्या या उद्देश्य नहीं होता। सेवाविनवृत्ति जीवन का एक नया पड़ाव होना चाहिए, न कि अचानक अपने बाला जमाने का। अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाएं। कोई किताब पढ़ें, कोई नया कौशल सीखें, कोई व्यक्तिगत परियोजना शुरू करें, परिवार के साथ यात्रा करें, स्वस्थ रहें या कोई शौक अपनाएं। आप अपना समय कैसे बिताते हैं, यह दशाती है कि आप भविष्य में अपना जीवन कैसे जिएंगे।

**मच्छर जानलेवा है, जागरूकता और स्वच्छता
ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार**

कातिलाल मांडोत

मच्छर आकार में भले ही बहुत छोटा जीव है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए इसका खतरा बेहद बड़ा है। दुनिया में अनेक गंभीर संक्रमण बीमारियों के प्रसार में मच्छरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जकारा पानी इंसेफालाइटिस, जीका, पीला बुखार और फाइलेरियासिस जैसी बीमारियां मच्छरों के माध्यम से फैलती हैं। इन बीमारियों के कारण हर वर्ष 30 लाख संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं और कई मामलों में स्थिति गंभीर भी हो जाती है। इसलिए मच्छर को केवल परेशान करने वाला कीट मानना उचित नहीं है। यह मानव जीवन के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विदेश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की ऐतिहासिक खोज की स्मृति में मनाया जाता है। 20 अगस्त 1897 को रॉस ने यह महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया कि मच्छर एनोफिलेज मच्छर मलेरिया के परजीवी को फैलाने में भूमिका निभाता है। इस खोज ने मलेरिया के संक्रमण और उसके नियंत्रण को समझने की दिशा में चिकित्सा विज्ञान को नई राह दिखाई। रॉस को बाद में वर्ष 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व मच्छर दिवस का उद्देश्य केवल इस वैज्ञानिक उपलब्धि को याद करना नहीं है, बल्कि लोगों को मच्छरजनित बीमारियों के खतरे और उनसे बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना भी है। यह दिवदिवस यह दिलाता है कि बीमारी फैलाने के बाद उपचार करने से बेहतर है कि मच्छरों के प्रजनन को रोककर बीमारी की आशंका को ही कम किया जाए। मलेरिया मच्छर से फैलने वाली सबसे पुरानी और गंभीर बीमारियों में से एक है। यह प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है और संक्रमित मादा एनोफिलेज मच्छर के काटने से फैलता है। बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं। समय पर जांच और उचित उपचार मिलने पर मलेरिया को इलाज संभव है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में यह गंभीर और जानलेवा रूप ले सकता है। डेंगू भी मच्छरजनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छरों से फैलती है। तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, मतली और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में डेंगू गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए लगातार या तेज बुखार होने पर चिकित्साीय सलाह लेना आवश्यक है। डेंगू की रोकथाम में मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में शामिल है। चिकनगुनिया और एडीज मच्छरों से फैलता है। इसमें बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जापानी इंसेफालाइटिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है। जीका वायरस भी एडीज मच्छरों के माध्यम से फैल सकता है और गर्भावस्था के दौरान विशेष चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा पीला बुखार और फाइलेरियासिस भी मच्छरों से फैलने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। मच्छरों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सामान्यतः मादा मच्छर ही मनुष्य और अन्य जीवों का रक्त चूसती हैं। मादा मच्छर की आंखों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। नर मच्छर मुख्य रूप से पौधों के रस और अन्य ननस्पति स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। मच्छर मनुष्य तक पहुंचने के लिए सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गंध और गंध जैसे संकेतों का उपयोग करते हैं। इसी कारण वे मनुष्यों को आसानी से खोज लेते हैं। मच्छरों की अलग-अलग प्रजातियों का व्यवहार और बीमारी फैलाने की क्षमता भी अलग होती है। इसलिए मच्छर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक निगरानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपाय करना आवश्यक है। मच्छरों के प्रजनन को रोकना का सबसे प्रभावी तरीका उनके प्रजनन स्थलों को समाप्त करना है। घरों के आसपास जमा पानी मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। कुलर, गमनें, पुराने टायर, खाली डब्बे, छत पर रखे पानी, बनी की टंकियां और अन्य बर्तन यदि खुले हों तो उनमें मच्छर पनप सकते हैं।

वन्दे मातरम् प्रेमः हकीकत या फसाना

छंदों पर आधारित यह गीत काफी लंबा भी है। चूँकि आम तौर पर केवल इसके पहले दो छंदों को ही आधिकारिक रूप से गाय जाया जाता रहा है, इसलिए देश के अधिकांश राजनेताओं और आम नागरिकों को भी इसके बाद के 4 छंद ठीक-ठीक याद नहीं होते हैं। लेकिन भाजपा के मामले में यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वह अन्य छंदों में भी राष्ट्रगीत के अपमान का तो आरोप लगाती है, जबकि खुद उसके अपने नेता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने में चूक जाते हैं। समय-समय पर भाजपा के नेताओं की इस गीत को लेकर अज्ञानता कैमरे पर भी उजागर हो गई है। एक टेलीवीजन लाइव डिबेट के दौरान, जब भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह दूसरों को हावदे मातरम्हू के छंदों की चुनौती दे रहे थे, तो एंकर ने उनसे स्वयं इसे गाने को कह दिया। वे अपने मोबाइल फोन में देखने के लिए राष्ट्रगीत की गलत पंक्तियाँ गाने लगे और धुन भी पूरी तरह भूल गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रवक्ता के पूर्व मंत्री बलदेव सिंह औलख से जब प्रश्नकर्ता ने हावदे मातरम्हू की कुछ पंक्तियाँ सुनाने को कहा, तो बलदेव असहज हो गए। उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस समय पूरा याद नहीं है।



निर्मल रानी
(लेखक)

काफ़ी कठिन है। 6 छंदों पर आधारित यह गीत काफी लंबा भी है। चूँकि आम तौर पर केवल इसके पहले दो छंदों को ही आधिकारिक तौर पर गाया जाता रहा है, इसलिए देश के अधिकांश राजनेताओं और आम नागरिकों को भी इसके बाद के 4 छंद कठस्थ याद नहीं होते हैं। लेकिन भाजपा के मामले में यह विवाद इसलिए भी बढ़ा हो जाता है क्योंकि वह अन्य दलों पर राष्ट्रगीत के अपमान को भी आरोप लगाती है, जबकि खुद उसके अपने नेता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने में चूक जाते हैं। समय-समय पर भाजपा के नेताओं की इस गति को लेकर अज्ञानता कैमरे पर भी उजागर हुई है। एक टेलीवीजन लाइव डिबेट के दौरान, जब भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह दूसरों को हारवदे मारत-हूँ गाने की चुनौती दे रहे थे, तो एंकर ने उनसे स्वयं इसे गाने को कह दिया। वे अपने मोबाइल फोन में देखने के बावजूद गीत की गलत पंक्तियाँ गाने लगे और धून भी पूरी तरह भूल गए।

हसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पूर्व कर्मी बलदेव सिंह औलख से जब पत्रकारिता ने हावदी मातृम्ह की कुलु पक्तिर्या सुनाने को कहा, तो वे बेह असहज हो गए। उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस समय पूरा ज्ञान नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर में भाजपा के मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, मंच पर राष्ट्रगीत गाते समय गलत धून और गलत वजन बज गया। कौमिस द्वारा इस बड़ी चूक पर हमला किए जाने के बाद राष्ट्रस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठीड़ की सावजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। कोटा, मेरठ और ग्यालियर जैसे कई शहरों में भाजपा के स्थानीय विधायकों और सांसदों के ऐसे सनेके वीडियो सामने आ चुके हैं, जहाँ वे वंदे मातरम् और राष्ट्रगान (जन गण मन) के बीच अंतर करने में प्रमित हो जाते हैं या गीत की पक्तियों को आपस में मिला देते हैं। हाल ही में गुजरे संसद



मानसून सेक के दौरान जब हावर्दे मातरम्हू को लेकर यात्रा कानून और अदालती विवाद परमाया, तो विश्व ने हावर्दे को घेरते हुए कहा कि हूजिन्होने द मातरम्हू को लेकर कड़े कानून बनाये हैं। हाकिम कहत यह है कि उन के अपने अहक और मंत्रियों को भी यह गति अपनाने द नहीं है। उधर मुस्लिम समुदाय के अन्दर इस गति को लेकर अलग-अलग रेटेक्षण और विचार हैं। हालाँकि समग्र इस्लाम समाज हावर्दे मातरम्हू मानन विरोध नहीं करता है परन्तु संजान कुछ लोग या कुछ धार्मिक संगठन को पूरे पाठ या कुछ विशिष्ट छंदों का आरोध करते हैं। जबकि अनेक अन्य इस्लाम नागरिक, प्रतिष्ठित लोग और पलाकार इस देशभक्ति के प्रतीक के रूप में महजता से गति भी हैं। द असल सलमानों के एक वर्ग के बंदे मातरम्हू विरोध करने के पीछे मुख्य रूप से धार्मिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक कारण हैं। एकेवरवाद के सिद्धांत पर

आधारित इस्लाम धर्म में केवल एक अल्लाह है। इबादत की अनुमति है। जबकि वेदों में मारुत का शाब्दिक अर्थ है 'हूँ', मैं आपकी वंदना/पूजा करता हूँ। हूँ होता है जहाँ देश को एक देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया है। जिनमेंयत उलेमा-ए-हिंद जैसे धार्मिक संगठनों का मानना है कि अल्लाह के अलावा किसी भी अन्य सत्ता, भूमि या मूर्ति के सामने झुकना या उसकी पूजा करना उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। कुछ इतिहासकारों और मुस्लिम विचारकों का मानना है कि इस उपन्यास में की प्रभुर्भूमि और कुछ अंशों में मुस्लिमता में विरोधी भावनाएँ निहित थीं, जिससे इस संगीत को लेकर ऐतिहासिक रूप से एक संघर्ष पैदा हुआ है। कई मुस्लिम नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों का यह तर्क भी है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 और 25 नागरिकों को अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उनका कहना है कि देशभक्ति संविधान

करने के लिए किसी को भी ऐसा गीत बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो उनकी धार्मिक आस्था से टकराता हो। हालांकि इस विषय में मुस्लिम समाज भी एकमत नहीं है। कुछ उलेमाओं का मानना है कि इसके क्षेत्र में मूर्तिपूजा और देवी स्वरूप की स्तुति शामिल है, इसलिए वे इसे गाने से परहेज करते हैं। यहाँ वजह यह थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ही इस गीत के केवल रूप में अपनी बात छोड़ें को ही राष्ट्रगीत की शुरुआत बनाया था। पहले दो छंदों में देश की प्राकृतिक सुंदरता (सुजला-सुफल) का वर्णन है, जिस पर का प्रगतिशील मुस्लिम संगठनों को कोई आपत्ति नहीं है। जबकि छंद उदासीन मुस्लिम, आम नागरिक और कलाकारों जैसे बिना किसी धार्मिक चरम के केवल अपनी मातृभूमि प्रति सम्मान और प्रेम के रूप में देखते हैं।

विचारों की लड़ाई है -दिमागी नक्सली

साल चुनौती उन विचारों और प्रचार-तंत्रों से है, जो युवाओं को लोकतांत्रिक बहस से निकालकर हिंसा, गंगा, विध्वंस और अराजकता की ओर धकेलते हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। युवा ऊर्जा यदि शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, उद्योगिता, कृषि, पर्यटन, खेल और सामाजिक सेवा में लगे तो वही ऊर्जा देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसके परीत यदि युवाओं के भीतर लगातार यह भावना मरी जाए कि व्यवस्था में कोई सुधार संभव नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाएं बेकार हैं और परिवर्तन का एकमात्र रास्ता हिंसा या विध्वंस है, तो यह मानसिकता विकसित और समाज दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। युवा मन स्वभावतः प्रश्न करता है। वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है और बदलाव की आकांक्षा रखता है। यही उसकी ताकत है। किन्तु इसी ऊर्जा को यदि तथ्यहीन प्रचार, आधी-अधूरी जानकारी और कट्टर वैचारिक प्रभाव दिखा देने लगे, तो रचनात्मक असंतोष विनाशकारी क्रोध में बदल सकता है। इसलिए सवाल युवाओं को चुप कराने का नहीं है, बल्कि उनके सवालों को सही दिशा देने का है।



जितेन्द्र कुमार सिन्हा
(लेखक)

दे श में समय-समय पर ऐसे शब्द और अवधारणाएँ चर्चा में आती हैं, जो समाज के भीतर चल रही किसी बड़ी बहस की ओर संकेत करती हैं। हूड्समिणी नक्सलीह भी ऐसा ही एक विवादस्पद और तीखा शब्द है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है, जिन पर हिंसक उग्रवाद, अराजकता या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिए बिना वैचारिक स्तर पर पुंवाओं को प्रमित करने, व्यवस्था के प्रति अंधी नक़रत पैदा करने या हिंसा को उचित ठहराने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करते समय एक बुनियादी सावधानी जरूरी है असहमति, सरकार की आलोचना, वैचारिक मतभेद और नक्सली या हिंसक उग्रवाद एक ही चीज़ नहीं हैं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना नागरिक अधिकार है। इसलिए किसी व्यक्ति या समूह को केवल उसके राजनीतिक विचारों के

कारण दिमागी नक्सली कहना उचित नहीं होगा। असल चुनौती उन विचारों और प्रचार-तंत्रों से है, जो युवाओं को लोकतांत्रिक बसस से निकालकर हिंसा, घृणा, विध्वंस और अराजकता की ओर धकेलते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी देशों में शामिल है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। युवा ऊर्जा यदि शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, उद्यमिता, कृषि, उद्योग, खेल और सामाजिक मुद्दों में लगे तो वही ऊर्जा देश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकती है। इसके विपरीत यदि युवाओं के भीतर लगातार यह भावना भरी जाए कि व्यवस्था में कोई सुधार संभव नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाएँ बेकार हैं और परिवर्तन का एकमात्र रास्ता हिंसा या विध्वंस है, तो यह मानसिकता व्यक्ति और समाज दोनों के लिये नुकसानदेह हो सकती है। युवा मन स्वभावतः प्रश्न करता है। वह अन्याय को खिलाफ आवाज उठाता चाहता है और बदलाव की आकांक्षा रखता है। यही उसकी ताकत है। लेकिन इसी ऊर्जा

को यदि तथ्यहीन प्रचार, आधी-अधूरी जानकारी और कटुट्ट वैचारिक प्रभाव दिनाशकरी कोथ में बदल सकता है। इसलिए सवाल युवाओं को चुप कराना क नहीं है, बल्कि उनके सवालों को सही दिशा देने का है। आज विचारों का प्रसार केवल किताबों, अखबारों और सार्वजनिक सभाओं तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन के माध्यम से कोई भी पढ़ेस कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संवाद को व्यापक बनाया है, लेकिन इसके साथ गलत सूचना, भ्रामक वीडियो, फर्जी दृष्टिकरण, संपादित तस्वीरें और भावनात्मक प्रचार की चुनौती भी बढ़ी है। किसी घटना का दस सेकेंड का वीडियो देखकर पूरा निष्कर्ष निकाल लेना, किसी मारल पोस्ट को बिना सत्यापन के सच मान लेना या किसी समुदाय के प्रति नफरत फैलाने वाली सामग्री को लगातार देखना व्यक्ति की सोच को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज के युवा के लिए डिजिटल

क्षेत्रता भी उतनी ही जरूरी है जितनी परंपरिक शिक्षा। उसे यह सीखना होगा कि अगर वायरल संदेश सच नहीं होता है तो हर तीखा भाषण तथ्यपूर्ण नहीं होता है। यदि किसी समाज में कोई विध्वंसकारी विचार फैल रहा है, उसका मुकाबला केवल प्रतिक्रियात्मक दमन से नहीं किया जा सकता है। इसके सामने बेहतर विचार, बेहतर शिक्षा और बेहतर अवसर रखने होंगे।

सर्वोभी को यह समझना होगा कि भारतीयों, बेरोजगारों, ग्रुथकारों, सामाजिक समसामानता या प्रशासनिक कमियों का समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रज्जुजर करके नहीं, बल्कि उन्हें प्रज्जुजर करके किया जा सकता है।

संसद, विधानसभाएं, न्यायपालिका, पोलिस, विश्वविद्यालय, स्थानीय सरकारें और नागरिक समाज, ये सभी लोकतांत्रिक परिवर्तन के रास्ते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था में कमी है तो उसके खिलाफ प्रभावजनक उठाए। यदि नीतिगत है तो प्रभावजनक उठाए। यदि प्रशासनिक है तो प्रभावजनक उठाए।

परंपरावाही है तो जवाब मांगिए। लेकिन

हिंसा और विध्वंस को परिवर्तन का साधन मानना अंततः उसी समाज को कमजोर करता है, जिसके सुधार की बात की जाती है। राष्ट्र-निर्माण की चर्चा में यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि देशभक्ति का अर्थ सरकार की हद नीति का समर्थन करना नहीं है। देश नागरिकों से बनता है, और नागरिकों को अपनी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। लोकतंत्र में असमर्थता कोई अपराध नहीं है, बल्कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। एक जिम्मेदार नागरिक वह है जो देश से प्रेम करते हुए उसकी कमियों पर भी सवाल उठाता है और सुधार का रास्ता सुझाता है। इसलिए युवाओं को दो अतियों से बचना होगा, एक ओर अंध-समर्थन और दूसरी ओर अंध-विरोध। देश को अंधभक्ति नहीं, जागरूक नागरिक चाहिए। भारत ने लंबे समय तक वागंधेय उग्रवाद और नक्सली हिंसा की चुनौती का सामना किया है। कई क्षेत्रों में हिंसा ने आम नागरिकों, सुशासन और विकास कार्यों को प्रभावित किया।

है। हिंसक उग्रवाद का स्पष्ट विरोध होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायर उठाकर नागरिकों या सुरक्षा बलों पर हमला करने को राजनीति में असहमति का सामान्य रूप नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसी के साथ वैचारिक बहस को भी हिंसक उग्रवाद के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय के छात्र का किसी आर्थिक नीति से असहमत होना, किसी लेखक का सरकार की आलोचना करना या किसी नागरिक का सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में नक्सली गतिविधि नहीं है। यही अंतर्-लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखता है। भारत आज विज्ञान, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में युवाओं के सामने अक्सर का एक विशाल संसार है। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि देश बदलने के लिए केवल नारों को जरूरत नहीं है, बल्कि कोशल और मेहनत को जरूरत है।

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक जितेन्द्र कुमार सिन्हा की चौथी कृति गयाआजी प्रकाशित होकर पाठकों के बीच आ चुकी है। 122 पृष्ठों में प्रकाशित यह पुस्तक गया की धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को सहज एवं सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। पुस्तक का मूल्य मात्र 2999 रुपये है और इसका प्रकाशन ऑरेंज बुक्स



पब्लिकेशन, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। भारी कलम एक श्रेण नहीं है। अत्यंत भारती धार्मिक चेतना में एक बलिष्ठ महत्त्वपूर्ण तीर्थभूमि है। यहाँ धर्म, मोक्ष, ज्ञान, आस्था और इतिहास का जड़ित प्रभाव दिखाई देता है। लेखक किन्दु कुमार सिन्हा ने इसी बहुआयामी पहचान को अपनी पुस्तक ढगया जीवित का विषय बनाया है। लेखक ने पुस्तक को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया है। छोटे-छोटे भागों के माध्यम से गंगा जी

धर्म, मोक्ष एत

से जुड़े धार्मिक एवं ऐतिहासिक विषयों को पाठकों के सामने रखा गया है। भाषा सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण है, जिसके कारण पुस्तक सामान्य पाठक के साथ-साथ धार्मिक एवं ऐतिहासिक विषयों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भी उपयोगी बन जाती है। पुस्तक में गीसासुर, भगवान विष्णु और उनके चरणचिह्न विष्णुपद, फल्यु नदी, विष्णुपद मंदिर, पितरों की मोक्ष-प्रक्रिया तथा गया जी के विभिन्न मोक्ष स्थलों का उल्लेख किया गया है। इन विषयों के माध्यम से लेखक ने गया की धार्मिक पहचान और उससे जुड़ी मान्यताओं को समझाने का प्रयास किया है। गया की धार्मिक पहचान की

और इतिहास पठनीय

स की संग कृति है गया

म भूमि पर

जी

निमित्त धार्मिक कर्मकांड करने आते हैं। पुस्तक में गया के विभिन्न मोक्ष स्थलों और उनके धार्मिक महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखक ने केवल धार्मिक मान्यताओं को सामने रखने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि गया की शहर के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा भी की है। इस दृष्टि से गया जी धार्मिक पुस्तक होने के साथ-साथ एक उपयोगी परिचयात्मक पुस्तक भी बन जाती है।

गया यात्रा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी भाषा है। लेखक ने कठिन धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों को बोझिल बनाने के बजाय सामान्य पाठक की समझ के अनुसार प्रस्तुत किया है।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित कर शीघ्र एनओसी दें: अंचलाधिकारी

प्रात : किरण संवाददाता

मोतिहारी पु.च. समाहरणालय स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में बुधवार को जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों तथा कार्य विभागों के अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने की।बैठक में जिलाधिकारी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि जिन विभागों द्वारा भूमि की मांग की गई है, संबंधित अंचलाधिकारी जमीन चिन्हित कर यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं।उप विकास



आयुक्त ने बताया कि जिले की 262 पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 132 स्थानों पर भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना शेष है। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को शीघ्र भूमि चिन्हित कर एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।बैठक में जिले के

112 हाट-बाजारों में अतिक्रमण की जानकारी भी दी गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को सूची के आधार पर जांच कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने तथा नियमानुसार अतिक्रमणवाद चलाने का निर्देश दिया।मनरेगा योजना के तहत जिले में 105 आंगनवाड़ी

सीओपी-डी कार्यक्रम के तहत स्कूल नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित

प्रात : किरण संवाददाता

बेतिया। सीओपी-डी (कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिमांड) कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्तर पर टीकाकरण संबंधी जागरूकता एवं मांग को मजबूत करने के उद्देश्य से स्कूल नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में नोडल शिक्षकों को कार्यक्रम के उद्देश्यों, उनकी भूमिका एवं समुदाय के साथ समन्वय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बच्चों के नियमित टीकाकरण के महत्व, टीकाकरण से वंचित एवं आंशिक रूप से टीकाकृत



बच्चों की पहचान, अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षणों ने बताया कि विद्यालय समुदाय और अभिभावकों तक स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है।ऐसे

गोसाई कुंड मेले की तैयारी तेज, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलिकॉप्टर सेवा पर जोर

बगहा। नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल गोसाई कुंड में जने पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। समुद्र तल से करीब 4,380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोसाई कुंड में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, आवागमन, स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलिकॉप्टर सेवा को महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। काठमांडू से गोसाई कुंड तक हेलिकॉप्टर के माध्यम से पहुंचने की सुविधा उपलब्ध रहती है। इससे श्रद्धालु कठिन और लंबी पैदल यात्रा से बचते हुए कम समय में गोसाई कुंड पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग, बच्चों के साथ यात्रा करने वाले और लंबी पैदल यात्रा में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा उपयोगी मानी जाती है। गोसाई कुंड धार्मिक आस्था के साथ-साथ नेपाल के प्रमुख पर्यटकीय स्थलों में भी शामिल है। जने पूर्णिमा के अवसर पर यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु पवित्र कुंड में स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के कारण इस पर्व के दौरान गोसाई कुंड में विशेष भीड़ रहती है।

750 ग्राम गांजा के साथ नेपाल का तस्कर गिरफ्तार

सुगौली। सुखा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुगौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 ग्राम गांजा के साथ एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार में संलग्न लोगों में हड़कंप मच गया है। थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए कार्रवाई की। इसी दौरान राजन मुखिया, पिता रमाकांत मुखिया, निवासी जीपूर, जिला बारा, नेपाल को पुलिस ने गांजा के साथ पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी नेपाल का रहने वाला है और उसके पास से बरामद गांजा को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किसके पास पहुंचाया जाना था। साथ ही नशे के इस्ते अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे धंधे में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

नशामुक्त भारत के संकल्प से गूंजा दीन दयाल हाई स्कूल परिसर

प्रात : किरण संवाददाता

सुगौली, पू.च.: प्रखंड के दीन दयाल हाई स्कूल परिसर में बुधवार को नशा मुक्त भारत अभियान एवं मिशन स्पंदन के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 6 से 20 अगस्त 2026 तक चल रहे हानशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियानह्म के तहत आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्वस्थ, सशक्त तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। देशभर में अभियान के माध्यम से 10 करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञाएं कराने का



लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीके मीना दीदी ने कहा कि नशा सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आपसी संबंधों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल लक्ष्य बनाने के प्रत्येक वर्ग को केवल व्यक्तिगत प्रयास तक सीमित रखने के बजाय प्रयास के प्रत्येक वर्ग को इसके विरुद्ध जागरूक होना होगा। अभियान के दौरान लोगों को नशे से पूरी तरह दूर

पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार-प्रसार हेतु ई-रिवशा

वाहनों को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी

प्रात : किरण संवाददाता

मोतिहारी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आमजनों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण द्वारा ई-रिक्षा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ई-रिक्षा जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को योजना एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सब्सिडी के संबंध में जागरूक करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत एक सरकार द्वारा पूर्व से दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर केंद्र सरकार की 30,000



की सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 10,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार 2 किलोवाट पर कुल 80,000 तथा 3 किलोवाट पर कुल 98,000 तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही यह अतिरिक्त सब्सिडी हफहले आओ, पहले पाओह के आभार पर उपलब्ध होगी तथा यह लाभ मार्च 2027 तक ही दिया जाएगा। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि

के द्रों का निर्माण लंबित बताया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि चिन्हित कराने एवं एनओसी प्राप्त करने का निर्देश दिया। वहीं, स्कूलों में संचालित 60 आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में निर्देश दिया गया कि यदि विद्यालय परिसर में पर्याप्त जगह उपलब्ध हो तो वहीं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कमरा निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाए।पंचायत सरकार भवन के लिए चिन्हित 14 जमीनों के भूमि विवाद का भी मामला बैठक में सामने आया। जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं

अंचलाधिकारी को विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार विवादों का शीघ्र समाधान निकालने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके निर्माण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।सिविल सर्जन ने बताया कि बंजरिया एवं रामगढ़वा अंचल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिले में 15 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्वयं भूमि चिन्हित कर अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए एनओसी प्राप्त करने का निर्देश दिया।

मेड़िहारी बीट में ग्रामीणों के साथ बैठक, वन्यजीवों से बचाव को लेकर किया जागरूक

प्रात : किरण संवाददाता

बगहा।। वन प्रमंडल-2 के वाल्मीकिनगर रेंज अंतर्गत मेड़िहारी बीट में वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर वन्यजीवों के संतर्पित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक का उद्देश्य ग्रामीणों को वन्यजीवों की गतिविधियों के प्रति जागरूक करने के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी देना रहा। बैठक में ग्रामीणों ने क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही और उससे जुड़ी समस्याओं को वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने तथा जंगल एवं जंगल विभाग को देने के लिए कहा गया है।

बेतिया। सामुदायिक स्तर पर टीकाकरण को बढ़ावा देने की दिशा में सीओपीडी (कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिमांड) कार्यक्रम के तहत बगहा -1, प्रखंड की मझौआ और पतिलार पंचायतों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। दोनों पंचायतों में सभी पात्र बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित कर उन्हें शत-प्रतिशत टीकाकरण वाली पंचायत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इस उपलब्धि में पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सीओपीडी टीम के सामूहिक प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पतिलार पंचायत की मुखिया श्रीमती पुष्य मिश्रा एवं मझौआ पंचायत के मुखिया श्री रुदल प्रसाह ने सीओपीडी कार्यक्रम के साथ मिलकर अपने-अपने पंचायतों के परिवारों की बच्चों के नियमित



एवं समय पर टीकाकरण के लिए लगातार प्रेरित किया। जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से पात्र परिवारों तक पहुंच बनाकर बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया गया। आज की तारीख में दोनों पंचायतों के प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है, जो पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बगहावन

बाघ के हमले में तीन लोगों की मौत के बाद वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता

प्रात : किरण संवाददाता

बगहा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ की बढ़ती गतिविधियों और लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग की टीम लगातार गांव-गांव माइकिंग कर ग्रामीणों को वन्यजीवों से बचाव के लिए जागरूक एवं सतर्क कर रही है। ग्रामीणों से जंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बताया जाता है कि पिछले करीब 20 दिनों के अंदर बाघ के हमले में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से वीटीआर से सटे गांवों के ग्रामीणों में भय का माहौल है। खेतों में काम करने, मवेशियों के लिए चारा काटने और जंगल के आसपास जाने वाले लोगों को

विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। बता दें, 15 अगस्त को भेरियारी क्षेत्र में हुई घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान और तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार भेरियारी में खेत में मवेशियों के लिए घास काटने के दौरान बाघ ने विजय हलदर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे वन कर्मियों के साथ मारपीट भी की थी। वाल्मीकिनगर रेंज के रेंजर सत्यम कुमार ने बताया कि बाघ के हमलों को देखते हुए वीटीआर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार माइकिंग कर लोगों को सतर्क एवं जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को जंगल और उसके आसपास जाने से बचने तथा वन्यजीव की गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को देने के लिए कहा जा रहा है। विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा रही है।

बाघ के हमले में किसान की मौत के बाद सड़क जाम, 34 नामजद समेत 350 अज्ञात पर केस



प्रात : किरण संवाददाता

बगहा। वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के भेड़िहारी बंगाली टोला में बाघ के हमले में किसान विजयकिनगर थानास्थल सह सड़क जाम और हंगामे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वनपाल आशीष कुमार के आवेदन पर वाल्मीकिनगर थाने में 34 नामजद समेत करीब 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कांड संख्या 125/26 दर्ज कर मामले को जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के नुकसान पहुंचाने समेत अपराधियों में अनुसूच, 15 अगस्त को विजय हालनगर की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को भेड़िहारी हाईस्कूल के सामने मुख्य सड़क पर रखकर वाल्मीकिनगर-मदनपुर मुख्य मार्ग को

जाम कर दिया था। सूचना मिलने पर वनपाल आशीष कुमार वनरक्षी कुंदन कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वनपाल और वनरक्षी के साथ मारपीट की। वनपाल की वही फाड़ने और जान से मारने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। आवेदन में बताया गया है कि भीड़ को समझाने और बीच-बचाव करते पहुंचे वाल्मीकिनगर थानास्थल सह पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। उत्र भीड़ ने वन विभाग की सुरक्षा गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर सड़क पर पलट दिया और उसमें आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने किसी तरह वनपाल को भीड़ से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार, मामले में विधि-विरुद्ध जमावड़ा, सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, जानलेवा हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अपराधों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसडीपीओ निहार भूषण ने कहा की पुलिस घटना से जुड़े वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को पहचान कर आगे की कार्यवाई मे जुटी है।

गन्ने के खेत में मिला चार वर्षीय अज्ञात बच्ची का शव, इलाके में सनसनी

बगहा। बगहा पुलिस जिला के घनहा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर गन्ने के खेत से करीब चार वर्षीय अज्ञात बच्ची का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। शव तमकुहवा चौक के समीप बजाज एंजेंसी के सामने दक्षिण दिशा में स्थित गन्ने के खेत से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कुछ लोगों की नजर गन्ने के खेत में पड़े बच्ची के शव पर पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल घनहा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र को घेरकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। शव का कटाव जारी रहा। इससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। 109 घर और स्कूल नदी में विलीन मधुबनी के सीओ नंदलाल राम ने बताया कि चिउरही पंचायत में अब तक 109 घर और एक सरकारी स्कूल नदी में विलीन हो चुके हैं। कटाव से प्रभावित परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। वहीं, किसानों होने वाले परिवारों के पुनर्वसन के लिए भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। 12022-23 में भी 300 घर हुए थे विस्थापित ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में मधुबनी प्रखंड की सिसई पंचायत के वीरता गांव में भी गंडक नदी के कटाव से करीब 300 घर नदी में विलीन हो गए थे।

प्रात : किरण संवाददाता

बगहा। नेपाल में सर्पदंश की समस्या अब केवल तराई क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गई है। हाल के वर्षों में पहाड़ी और पर्वतीय जिलों में भी जहरीले सांपों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण सांपों का आवास ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जिससे वीके अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले पहाड़ी इलाकों में भी सर्पदंश का खतरा बढ़ गया है। नेपाल के राष्ट्रीय आवाद जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन 14 अप्रैल 2026 से जून के अंत तक सर्पदंश से कम से कम 22 लोगों की मौत और 320 लोग घायल हुए थे।

महिला की हत्या कर गन्ने मे छिपाया

हरसिद्धि। थाना क्षेत्र के गड्डपुर सरेह इलाके में बुधवार को एक महिला की निर्मम हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंके जाने से हड़कंप मच गया। मुख्य सड़क किनारे लगे गन्ने के खेत में शव मिलने की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने मामले की जानकारी तत्काल हरसिद्धि थाना को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम को बुलाया गया, जिसने स्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर फिंगरप्रिंट और अन्य तकनीकी प्रतीक्षणों के लिये अस्थि सैमपल कब्जे में लिए। प्रारंभिक पहचान में मृतका पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव निवासी झमन मिश्र की पत्नी, 50 वर्षीय नगमा खातून बताई जा रही हैं। पुलिस ने मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सरेह अस्पताल भेज दिया गया है। हरसिद्धि थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि हत्या के पीछे घरेलू विवाद या रंजिश की आशंका जताई जा रही है और इस क्रम में मृतका के एक करीबी रिश्तेदार पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि जांच हर पहलू से वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से की जा रही है। जांच टीम लोगों से पूछताछ कर रही है तथा कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की भूमिका स्पष्ट होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस संबंध में कोई आवेदन नहीं मिला है; आवेदन प्राप्त होने पर साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।



संक्षिप्त

समाचार

आस्था और जुगाड़ का मिलन: आखिर एम-सील बना कांवड़ यात्रा 2026 का एक गुमनाम हीरो?



अपनी पवित्र तीर्थयात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ संपन्न हुई, एक अप्रत्याशित घरेलू चीज इस सीजन के गुमनाम हीरो के रूप में उभरी है- एम-सील। हालांकि यह वार्षिक यात्रा मुख्य रूप से अटूट आध्यात्मिक भक्ति द्वारा संचालित होती है, लेकिन जमीन पर इसकी लॉजिस्टिक (प्रबंधन) सफलता पारंपरिक भारतीय जुगाड़ को एक बहुत बड़ा श्रेय देती है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िये, गंगा नदी (आमतौर पर हरिद्वार, गौमुख या सुल्तानगंज में) से पवित्र जल एकत्र करते हैं और इसे अपने स्थानीय मंदिरों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस तीर्थयात्रा के नियम बहुत सख्त हैं-पवित्र जल के पात्र (बर्तन) को कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए, और एक बूंद भी पानी नहीं छलकना चाहिए। कांवड़िये अपने दोस्तों के साथ भगवान में अपनी अटूट आस्था के साथ-साथ उबड़-खाबड़ रास्तों और मानसून के कठिन मौसम में रिसाव-मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एम-सील की सीलिंग शक्ति पर अपना अपार भरोसा जताया है।

हैदराबाद में 36 टन मिलावटी ची जव्त, खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया विशेष अभियान

हैदराबाद, एजेंसी। हैदराबाद में 36 टन मिलावटी ची जव्त किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, हैदराबाद खाद्य मिलावट निगरानी टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया। हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जानार ने बताया कि टीमों ने निरीक्षण के दौरान पता लगाया कि नकली, निम्न गुणवत्ता की सामग्री और खतरनाक, अवैध रासायनिक पदार्थों से सिंथेटिक घी बनाया जा रहा था। इस दौरान टीम ने 36 टन मिलावटी घी, क्रीम (कच्चा माल), पाम आयल, वनस्पति, नकली घी के फ्लेवर, स्टार्च, केमिकल जव्त किए। विस्तृत प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए शूक के लिए ही नमूने एकत्र किए। मिलावटी घी शुद्ध देखी घी के नाम पर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा था।

ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ से बढ़ेगी हरियाली, पार्कों और ग्रीन बेल्ट के स्वरखाव पर फोकस

ग्रेटर नोएडा, एजेंसी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाते जा रहा है। इस पर करीब 12 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। प्राधिकरण ने सेक्टर चाई-5, ओमिक्रान-एक ए, केपी-2, केपी-3, ओमिक्रान-3, चाई-3, ज्यू-एक, स्वर्ण नगरी और ईकोटेक-एक समेत 9 सेक्टरों में पार्कों, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज और सड़कों के किनारे हरियाली के विकास व रख रखाव के लिए करोड़ों रुपये के टेंडर जारी किए हैं। सेक्टर चाई-5 की 6 लेन सड़क के सेंट्रल वर्ज और हरित पट्टी के विकास व एक साल तक के रख रखाव पर 70.21 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं ओमिक्रान-एक ए, ज्यू-3, साइट-5 और ओमीक्रान-एक ए बैक साइड के सेंट्रल वर्ज में पौधारोपण और दो साल तक रख रखाव के लिए 1.09 करोड़ रुपये का खर्च किए जाएंगे। में दो साल तक के रख रखाव पर 1.24 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

भारत टू-स्टेट फॉर्मूले का समर्थक फलस्तीनी मंत्री से मिलीं सचिव प्रिया रंगनाथन, कहा- गाजा की स्थिति चिंताजनक

यरुशलम, एजेंसी। भारत ने फलस्तीन में बातचीत से दो-राज्य समाधान के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय की सचिव प्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन लोगों के लिए देश के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। रंगनाथन 16 से 21 अगस्त तक मिस्त्र, फलस्तीन और लेबनान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मंगलवार को रंगनाथन ने फलस्तीन की विदेश मामलों और प्रवासी मंत्री वर्सेन अघाबेकियन शाहिन से मुलाकात की। उन्होंने गाजा में गंभीर मानवीय स्थिति पर भारत की चिंता व्यक्त की। भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक्स पर बताया कि दोनों पक्षों ने भारत-फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इसमें उनके व्यापक विकास सहयोग पहल भी शामिल थे। भारत ने बातचीत से दो-राज्य समाधान के लिए अपने समर्थन पर जोर दिया। गाजा में मानवीय स्थिति को निरंतर सहायता और कूटनीति से सुलझाने का महत्व बताया। भारत इस्राइल और फलस्तीन के लिए मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से रहने वाले दो-



राज्य समाधान का समर्थन करता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। दोनों नेताओं ने फलस्तीन की वर्तमान स्थिति और गाजा के घटनाक्रम पर विशेष ध्यान दिया। मानवीय जरूरतों और भारत की विकास सोझेदारी पर भी चर्चा हुई। रंगनाथन ने फलस्तीन लोगों और बातचीत से दो-राज्य समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। संवाद और कूटनीति के

माध्यम से संघर्ष के स्थायी राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता-निर्माण से संबंधित चल रही पहलों की भी समीक्षा की गई। फलस्तीनी विदेश मंत्री ने जनवरी 2026 में भारत की अपनी सफल यात्रा को याद किया। उन्होंने भारत के निरंतर समर्थन के लिए सराहना व्यक्त की। यह समर्थन विकास परियोजनाओं, क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों और छात्रवृत्तियों के माध्यम से दिया जाता है।

सिटिंग-गेटिंग फॉर्मूले से मौजूदा विधायकों को मिला मौका, उत्तराखंड में भाजपा समन्वय से साधेगी हैट्रिक के समीकरण

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड में सरकार और संगठन के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय के रथ पर सवार होकर भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में दमदार तरीके से खम ठेकने जा रही है। तालमेल के साथ होने वाले इस शक्ति प्रदर्शन में लोकसभा के पांच और राज्यसभा के तीन सदस्यों यानी सभी आठ सांसदों की भूमिका योगक्षेम की रहने वाली है। यानी, विधानसभा सीटों की मौजूदा संख्या को सुरक्षित रखने के साथ उसमें वृद्धि करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वहीं, सिटिंग-गेटिंग के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ने के संकेत देकर पार्टी ने वर्तमान 47 विधायकों को राहत दे दी है। इससे उन विधायकों को भी संभलने का मौका मिला है, पार्टी के सर्वे में जिनकी स्थिति नाजुक आंकी गई है।

उत्तराखंड में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के समीकरण साधने के लिए विस्तर्रीय समन्वय भाजपा की रणनीति का खास हिस्सा बन गया है। इसे मजबूत किलेबंदी के रूप में देखा जा रहा है।

शिमला में भारी बारिश और भूस्खलन ने किया बेहाल: चार भवनों पर मंडराया खतरा, गाड़िया क्षतिग्रस्त

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। शिमला में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अपर लंबिधार-इंद्रनगर एंबुलेंस रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में एक वाहन भी आया है। सड़क बंद होने से स्कूल और कार्यालय जाने वाले लोगों को सुबह भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, लैंडस्लाइड से ऊपर की तरफ बने चार घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भग्नुत्कुर में भूस्खलन के कारण दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मंगलवार को रहे रही भारी बारिश के कारण शिमला के अपर लंबिधार-इंदर नगर एंबुलेंस रोड पर अचानक लैंडस्लाइड हो गया। पहड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ जाने के कारण यहां वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। लैंडस्लाइड की चपेट में एक वाहन भी आ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक लैंडस्लाइड के कारण सड़क के ऊपर बने चार घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में अगर जल्द सुर्क्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है। रामनगर वेलफेयर सोसाइटी, लंबिधार-इंदर नगर की ओर से पंचायती राज एवं ग्रामीण



लैंडस्लाइड वाले स्थान पर जल्द रिटेनिंग वॉल यानी सुरक्षा दीवार लगाने का आग्रह किया गया है, ताकि ऊपर बने घरों को सुरक्षित किया जा सके। शिमला में दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के बाद छोटा शिमला, समरहिल समेत अन्य क्षेत्रों में छह पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरने से कहीं वाहन इसकी चपेट में आए तो कहीं भवनों को खतरा पैदा हो गया। वर्षा के कारण जमीन में नमी बढ़ने से पेड़ों के गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। राज्य सचिवालय में एक पेड़ गिरा है और दूसरा पेड़ गिरने के कगार पर है। इसे गिराने का काम चला है। छोटा शिमला क्षेत्र में एक पेड़ गिरने से सड़क किनारे खाड़ा वाहन चपेट में आ गया। इससे वाहन को नुकसान पहुंचा।

वशिष्ठनगर योजना को शासन से मिली मंजूरी, स्टार्टअप्स को एलडीए देगा 50 एकड़ जमीन

लखनऊ, एजेंसी। आगरा एक्सप्रेसवे के निकट आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने व रोजगार

उद्यम स्थापित होने से क्षेत्र का आर्थिक विकास होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण



के अवसर सृजित करने के लिए वशिष्ठ नगर योजना के प्रस्ताव पर शासन की मुहर लग गई है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण योजना में स्टार्ट अप के लिए भारत सरकार के एमएसएमई विभाग की 50 एकड़ जमीन देगा। सूक्ष्म, लघु व मध्यम

योजना के तहत आगरा एक्सप्रेसवे पर 6580 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार आवासीय योजना विकसित की जा रही है। इस क्षेत्र में ही वशिष्ठ नगर योजना आकार लेगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, इसमें विशेष तौर से

आर्थिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक, लाजिस्टिक व व्यावसायिक क्लस्टर नियोजित किए जाएंगे। मंगलवार को वशिष्ठ नगर योजना का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे शासन ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत स्वीकृत किया है। योजना आगरा एक्सप्रेसवे के पास 1035 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी। इसके लिए ग्राम-रेवरी, भलिया, गहलवारा, आदमपुर इन्दवारा, बहरू व जलियामऊ की भूमि चिन्हित हुई है। आने वाले समय में योजना उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के विजन को साकार करते हुए राजधानी को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सल्लाई चैन से जोड़ेगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि

वशिष्ठ नगर में औद्योगिक, लाजिस्टिक व आर्थिक गतिविधियों के लिए नए जोन विकसित किये जाएंगे। एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना के तहत 50 एकड़ भूमि पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित होंगे। इससे राजधानी में स्टार्ट अप को ब?वा मिलेगा और युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर एक ही मंच पर मिलेंगे। वशिष्ठ नगर योजना आगरा एक्सप्रेसवे, मोहान रोड, लिंक एक्सप्रेसवे व वरुण विहार योजना जैसे महत्वपूर्ण कारिडोर से सीधे कनेक्ट होगी। इससे उद्योग, वेंयरहाउसिंग, लाजिस्टिक्स एवं परिवहन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। शासन की मंजूरी के बाद अब किसानों से सहमति व अन्य माध्यमों से भूमि जुटाव का कार्य शुरू किया जाएगा। भूमि लेने में लगभग 1328 करो? रुपये खर्च होंगे।

अबू अल-दुहर एयरबेस पर इस्राइली हमले से तनाव, क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा

यरुशलम, एजेंसी। सीरिया के इदलिव प्रांत स्थित अबू अल-दुहर एयरबेस पर इस्राइली हवाई हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। ने हमलों को सीरिया की संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और 1974 के डिसइंजेजमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। इस्त्राइल ने अपने कदम को सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जोड़ा है, जबकि अमेरिका ने हमलों को अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ाने वाला बताया है। सीरिया, जॉर्डन, कतर और तुर्की ने भी अलग-अलग तरीके से हमलों पर आपत्ति जताई है। एक बयान में के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस्त्राइली हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। मंत्रालय ने ऐसी किसी भी कार्रवाई को पूरी तरह खारिज किया, जो सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती हो। मंत्रालय ने कहा, सीरिया की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या उसकी सुरक्षा और स्थिरता के लिए पैदा किए जा रहे खतरों को पूरी तरह से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरियाई क्षेत्र में इस्त्राइल की ओर से लगातार किए जा रहे हमले अंतरराष्ट्रीय कानून और सीरिया तथा इस्त्राइल के बीच 1974 में हुए डिसइंजेजमेंट एग्रीमेंट यानी सेनाओं की वापसी संबंधी समझौते का खुला उल्लंघन हैं। मंत्रालय ने कहा, मंत्रालय ने सीरिया की स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में,श्व के अड्डा रख को दोहराया। साथ ही, सीरियाई लोगों के साथ एकजुटता जताई और सुरक्षा, शांति, सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा विकास की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सीरियाई क्षेत्र पर बार-बार हो रहे हमलों को रोकने और तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने

1600 घर खरीदारों के लिए गुडन्यूज, 19 साल से अटके अंसल प्रोजेक्ट को लेकर आई राहत भरी खबर

गाजियाबाद, एजेंसी। करीब 19 साल से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे अंसल हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब 1,600 खरीदारों की उम्मीदों को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राहत की उम्मीद नजर आ रही है। अदालत की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद ने जीडीए अधिकारियों के साथ अंसल प्रोजेक्ट की साइट का निरीक्षण किया। परियोजना की मौजूदा स्थिति, निर्माण में आ रही अड़चनों और लंबित स्वीकृतियों की जानकारी ली और घर खरीदारों से भी बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि करीब 1,600 खरीदार 19 वर्षों से अपने प्लैट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार और जीडीए को संयुक्त रूप से बैठक कर डेवलपमेंट लाइसेंस के नवीनीकरण और संशोधित भवन नक्शों की मंजूरी पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। साथ ही निर्णय की जानकारी अदालत के समक्ष रखने को कहा था। इसी क्रम में प्रमुख सचिव का साइट निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हमारा एक्शन सही था, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से हैरान तुकाराम मुंडे; एफडीए पर लगा था 5 लाख का जुर्माना

मुंबई, एजेंसी। पुणे की एक मिठाई दुकान के लाइसेंस सस्पेंशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। इस पुरे घटनाक्रम पर



महाराष्ट्र कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का यह आदेश उनके लिए हैरान करने वाला है, लेकिन विभाग अपनी कार्रवाई पर पूरी तरह कायम है और आदेश की लिखित कॉपी मिलने के बाद इसके खिलाफ आगे कानूनी विकल्प अपनाएगा। मामले की शुरुआत 12

जून को हुई, जब एफडीए की टीम ने पुणे की एक मिठाई दुकान का निरीक्षण किया और स्वच्छता व हाइजीन में भारी कमियां पाते हुए इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद दुकान द्वारा कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने



पर 13 जुलाई को दोबारा जांच की गई, जिसमें 98 प्रतिशत नियमों का पालन (36 में से 35 पैरामीटर सही) पाया गया। इसके बावजूद लाइसेंस सस्पेंशन जारी रहने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सस्पेंशन को रद्द कर दिया, दुकान को तुरंत काम फिर से

शुरू करने की इजाजत दी और खर्च को 30 दिनों के भीतर दुकान मालिक को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपने विभाग के फैसले का बचाव करते हुए खर्च कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा, यह सिर्फ कागजी नियमों की अनदेखी का मामला नहीं था, बल्कि फूड पॉजिनिंग की एक गंभीर घटना थी। इस दुकान से मिठाई खाने के बाद कई ग्राहक बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लैब जांच में सैपल असुरक्षित पाए गए थे। उन्होंने कहा, जनस्वास्थ्य के हित में उठाया गया हमारा कदम पूरी तरह सही था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। फिलहाल हम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश की समीक्षा करने के बाद हम अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तुकाराम मुंडे ने कहा, मुझे लगता है कि यह सच में बहुत जरूरी है। सपोर्ट के अलावा, हिस्सा लेना भी जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि यह एक पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इस तरह कदम उठा रहे हैं। इसे एक हेल्दी और मजबूत इंडिया, एक सुपरपावर बनाना है, तो हमारे पास एक हेल्दी इंडिया होना चाहिए।

पंजाब लाए गए बंबीहा गैंग के 3 गुर्गे, मलेशिया में छिपे थे; हत्या-रंगदारी और विस्फोटक मामलों में थे वांटेड

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब पुलिस ने विदेश में छिपकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे गैंग्स्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े तीन वांछित आरोपितों को मलेशिया से भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग की ओवरसीज एक्टिविटी टैंकिंग एंड एनर्सेट्रेशन सेल (ओएफटीईसी) ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से तीनों का प्रत्यर्पण कराया। तीनों आरोपितों को दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें पंजाब लाकर आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस बेहेबल, अजय सिंह और पवंदीप सिंह के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ हत्या, रंगदारी, विस्फोटक से जुड़े मामलों के साथ-साथ लुथियाना में हैंड ग्रेनेड से धमाका करने की साजिश में भी तलाश थी। ग्रेनेड मामलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से जुड़े तार भी सामने आए हैं। दो दर्जन से ज्यादा मामलों में वांछित होने की जानकारी पुलिस जांच में सामने आया है कि विदेश भागने के बाद आरोपित मलेशिया में छिपकर रह रहे थे। पंजाब में उनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार इन आरोपितों के खिलाफ दो दर्जन से अधिक मामलों में कार्रवाई और रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी है। अब भारत वापस लाए जाने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके पूरे नेटवर्क, विदेश में मदद करने वाले लोगों और पंजाब में सक्रिय साथियों के बारे में जानकारी जुटाएगी। पंजाब पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ओएफटीईसी की टीम लगातार विदेशों में छिपे वांछित अपराधियों की निगरानी कर रही है। केंद्रीय एलिया के समन्वय से मलेशिया में मौजूद इन तीनों आरोपितों का पता लगाया गया और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की गई। तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है।

अबू अल-दुहर एयरबेस पर इस्राइली हमले से तनाव, क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा



क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। नेतन्याहू कार्यालय ने बताया यथास्थिति का यह बयान इदलिव में अबू अल-दुहर एयरबेस पर इस्राइली हमलों की खबरों के बाद आया। हमलों के बाद इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इस्त्राइल और सीरिया सुरक्षा मामलों में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए थे। एक्स पर एक पोस्ट में नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि सीरिया अलेप्पो के पास एक एयरबेस पर तुर्की सैनिकों को तैनात करने की अनुमति देकर इस समझौते को तोड़ने की कगार पर था। बयान में कहा गया, इस्त्राइल और सीरिया सुरक्षा मामलों में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए थे, जिसे सीरिया अलेप्पो के पास एक एयरबेस पर तुर्की सैनिकों को तैनात करने की अनुमति देकर तोड़ने की कगार पर था।